भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम फरवरी, 2019

संख्या का० आ० 3/के० अ० 49/2016/धा० 84/2019.— निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 49), की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य न्यायमूर्ति, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति, से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना सख्या का0आ0 66/के0अ0 49/2016/धा0 84/2018, दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना सख्या का0आ0 66/के० अ० 49/2016/धा0 84/2018, दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 में, "अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय" शब्दो के स्थान पर "प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 1st February, 2019

No. S.O. 3/C.A. 49/2016/S.84/2019.— In exercise of the powers conferred by section 84 of the Rights of Persons with Disabilities Act. 2016,(Central Act 49 of 2016), the Governor of Haryana shall with the concurrence of the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. S.O. 66 / C.A. 49 / 2016 / S. 84 / 2018, dated the 9th October, 2018 namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. S.O. 66/ C.A. 49/2016/ S.84/2018, for the words "Additional Judge", the figure and words "1st Additional Sessions judge" shall be substituted.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

8545—L.R.—H.G.P., Pkl.